

STOP

STOP Trafficking and Oppression of children & women



Azim Premji
Philanthropic
Initiatives

शिक्षा

पुस्तक

रमोला भर चैरिटेबल ट्रस्ट

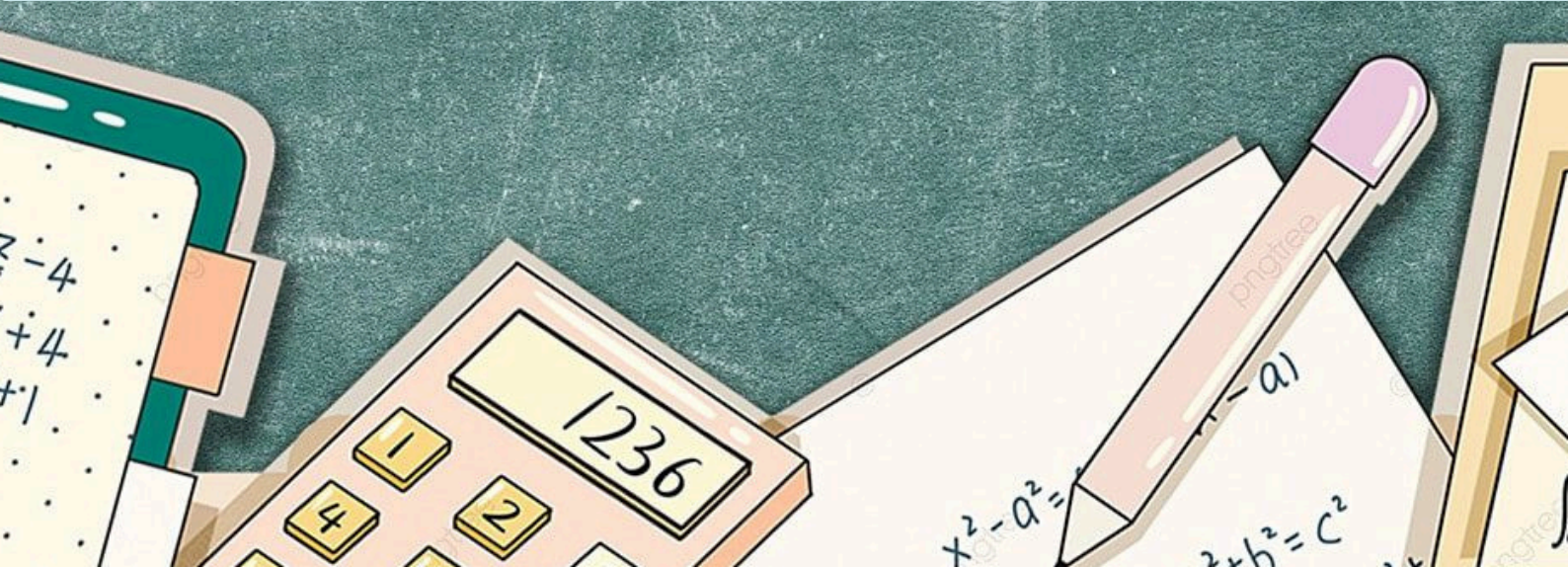


आभार

हम मैनुअल को पूरा करने में उनके महत्वपूर्ण समर्थन और अंतर्दृष्टि के लिए प्रोफेसर रोमा देबब्रता (STOP के अध्यक्ष और संस्थापक) के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम अपने सलाहकार श्री अमिताव भट्टाचार्य, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, भारत सरकार के आभारी हैं, जिन्होंने हैंडबुक के प्रकाशन के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

हमारी पूरी कवायद के पीछे प्रेरणा हमारे सम्मानित ट्रस्टी श्री डी. चक्रवर्ती थे जिनके अथक समर्थन ने प्रकाशन को दिन के उजाले में देखना संभव बना दिया। ये हैंडबुक अजीम प्रेमजी परोपकारी पहल की प्रेरणा के बिना संभव नहीं होती, जिसने STOP टीम को इस परियोजना को साकार करने के लिए प्रेरित किया।

हम उल्लिखित सभी हितधारकों के साथ-साथ संपूर्ण स्टॉप टीम के समर्पण के लिए उनके अथक प्रयासों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं।



सामग्री नाष्टिका

- परिचय
- भारत में शिक्षा की स्थिति
- शिक्षा की संरचना
- निरक्षरता के परिणाम
- ड्रॉप आउट
- कल्याणकारी योजनाएँ



परिचय



क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा सफलता की कुंजी क्यों है?


शिक्षा न केवल हमारे ज्ञान के आधार का विस्तार करती है बल्कि हमें कौशल और चरित्र लक्षणों में भी प्रशिक्षित करती है।

हम पुस्तक सामग्री को पढ़ते और अध्ययन करते हैं, लेकिन हम उस जानकारी को आत्मसात कर लेते हैं ताकि उसे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में लागू कर सकें। उदाहरण के लिए, हम कीटनाशकों और कीटनाशकों के बारे में सीखते हैं जो हमें एक समृद्ध उद्यान बनाने में मदद करते हैं, और इस प्रकार बागवानी में कौशल विकसित करते हैं। दूसरा उदाहरण यह है कि जब हम अंग्रेजी जैसी भाषाओं का अध्ययन करते हैं, तो हम अंग्रेजी में पढ़ने, लिखने और बोलने का कौशल विकसित करते हैं। इस प्रकार ये अर्जित कौशल हमें नौकरी पाने और एक सफल जीवन जीने के योग्य बनाते हैं।


शैक्षिक ज्ञान हमें अपनी राय और राजनीतिक विचार उत्पन्न करने में भी मदद करता है जो हमें निर्णय लेने में मदद करता है, और एक महत्वपूर्ण सोच की सुविधा देता है जो किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है और हमें हानिकारक कदम उठाने से रोक सकता है।

शिक्षा हमें चारित्रिक गुणों जैसे सामाजिक रूप से अपेक्षित आचार संहिता, विनम्रता जैसे व्यवहार, दूसरों के साथ धैर्य, हमारी दैनिक दिनचर्या का अनुशासन और संगठन, और नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का निर्माण करने में भी मदद करती है जिन्हें हमें अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अपने व्यक्तित्व में अपनाना चाहिए। देश की।


भारत में शिक्षा की स्थिति




भारत ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाने और स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या को कम करने में काफी प्रगति की है।



इन उपलब्धियों को प्रमुख कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों जैसे बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम (2009), राष्ट्रीय प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) नीति (2013) से बल मिला है। हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।



अनुमान है कि 2014 में स्कूल से बाहर रहने वाले 6.1 मिलियन बच्चों की संख्या 2006 में 13.46 मिलियन से कम हो गई है। 100 छात्रों में से, 29 प्रतिशत लड़कियाँ और लड़के प्रारंभिक शिक्षा का पूरा चक्र पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, और अक्सर वे सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले बच्चे होते हैं। . (स्रोत: एसआरआई-आईएमआरबी सर्वेक्षण, 2009 और 2014)



लगभग 50 प्रतिशत किशोर माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, जबकि लगभग 20 मिलियन बच्चे प्री-स्कूल नहीं जाते हैं। (स्रोत रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रेन 2013-2014 एमडब्ल्यूसीडी)



प्राथमिक विद्यालय जाने वाले आधे बच्चे - जो लगभग 50 मिलियन बच्चे हैं - ग्रेड के अनुरूप सीखने का स्तर हासिल नहीं कर पा रहे हैं। (स्रोत: राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, एनसीईआरटी 2017)

इसके अलावा, 5 साल की उम्र में बच्चों की स्कूल के लिए तैयारी अपेक्षित स्तर से काफी कम है। देश के कार्यक्रम की पहली छमाही में, परिचालन वातावरण में कई बदलाव हुए हैं, जिन्होंने इस बात पर प्रभाव डाला है कि यूनिसेफ इंडिया शिक्षा कार्यक्रम आगे कैसे संचालित होगा।

भारत में बाल अधिकार

6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 ए)

छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 45)

भारत में शिक्षा की संरचना

प्राथमिक
(6 से 10 वर्ष)

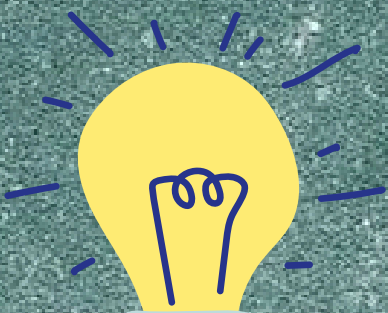
उच्च प्राथमिक
(11-13 वर्ष)

माध्यमिक
(14-15 वर्ष)

उच्च माध्यमिक
(16-17 वर्ष)

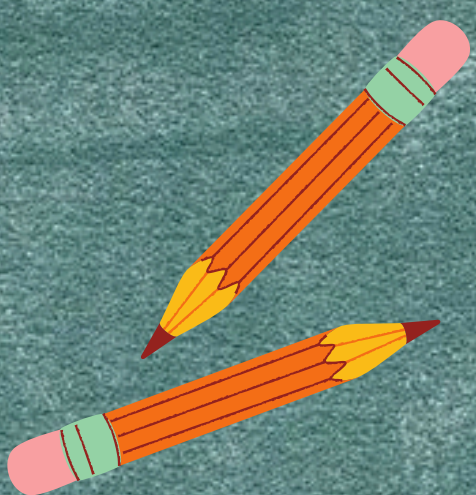
यूजी डिग्री (अंडर-
ग्रेजुएशन) या
व्यावसायिक प्रशिक्षण

पीजी डिग्री (पोस्ट
ग्रेजुएशन)

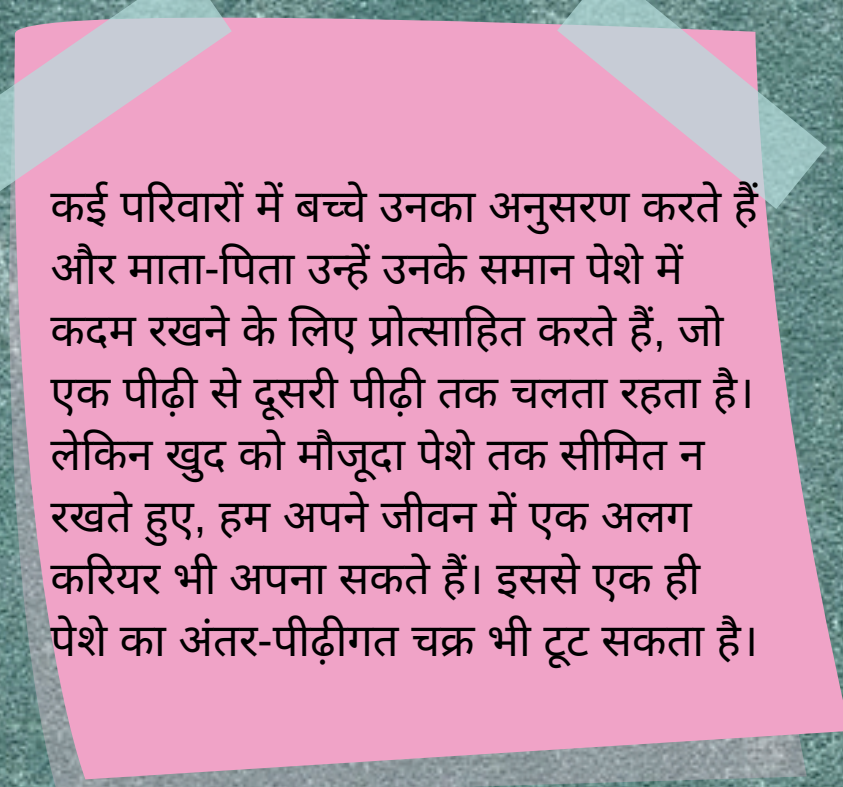


निरक्षरता के परिणाम

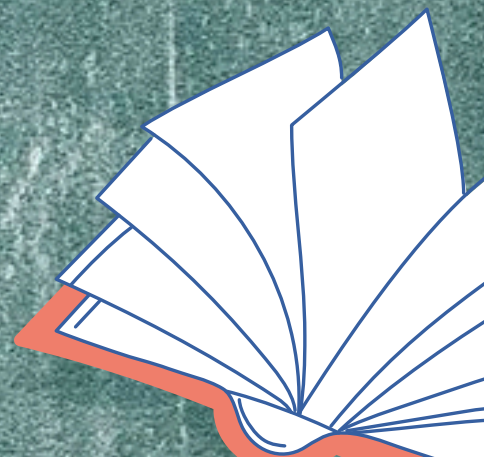
अंतर-पीढ़ीगत चक्र



जो माता-पिता कार्यात्मक रूप से निरक्षर हैं वे अक्सर शिक्षा से पहले काम को प्राथमिकता देते हैं, स्कूली शिक्षा के संबंध में उनकी उम्मीदें कम होती हैं, और जो माता-पिता प्राथमिक विद्यालय पूरा करने में असफल होते हैं उनके बच्चे उनके नक्शेकदम पर चलने और ऐसा ही करने की अधिक संभावना रखते हैं। इससे पीढ़ियों तक नुकसान का एक चक्र चलता रहता है।

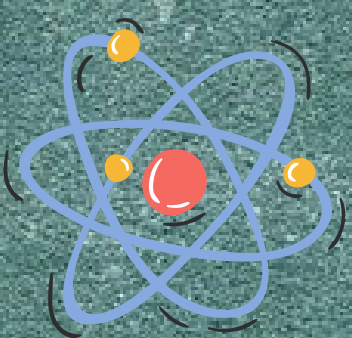


कई परिवारों में बच्चे उनका अनुसरण करते हैं और माता-पिता उन्हें उनके समान पेशे में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। लेकिन खुद को मौजूदा पेशे तक सीमित न रखते हुए, हम अपने जीवन में एक अलग करियर भी अपना सकते हैं। इससे एक ही पेशे का अंतर-पीढ़ीगत चक्र भी टूट सकता है।

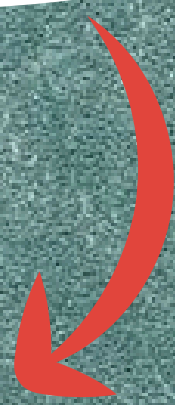





भारत में ड्रॉपआउट



2021-22 में, आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रीय औसत 12.6 प्रतिशत से अधिक हो गया। उदाहरण के लिए, 2021 में माध्यमिक स्तर पर बिहार में ड्रॉपआउट दर 20.46 प्रतिशत, गुजरात में 17.85 प्रतिशत, असम में 20.3 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 16.7 प्रतिशत, पंजाब में 17.2 प्रतिशत, मेघालय में 21.7 प्रतिशत और कर्नाटक में 14.6 प्रतिशत थी। -22. यूनिसेफ ने पाया कि भारत में 33 प्रतिशत लड़कियाँ घरेलू काम के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि कई बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं, वे अपने परिवार के साथ मजदूर के रूप में काम करने लगते हैं या घरेलू सफाई कार्यों में लग जाते हैं।



उच्च विद्यालय छोड़ने की दर भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। जो छात्र हाई स्कूल छोड़ देते हैं वे उस स्तर से आगे अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकते हैं। इससे उच्च शिक्षा हासिल करने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के उनके अवसर सीमित हो जाते हैं। इसके अलावा, हाई स्कूल छोड़ने वालों में उच्च शिक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और योग्यता होने की संभावना कम होती है। उन्हें कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रम की मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट दर बढ़ जाएगी।



हमने इससे क्या सीखा:

1. स्कूल छोड़ना एक बुरा विकल्प है क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत विकास और प्रगति को बाधित करता है

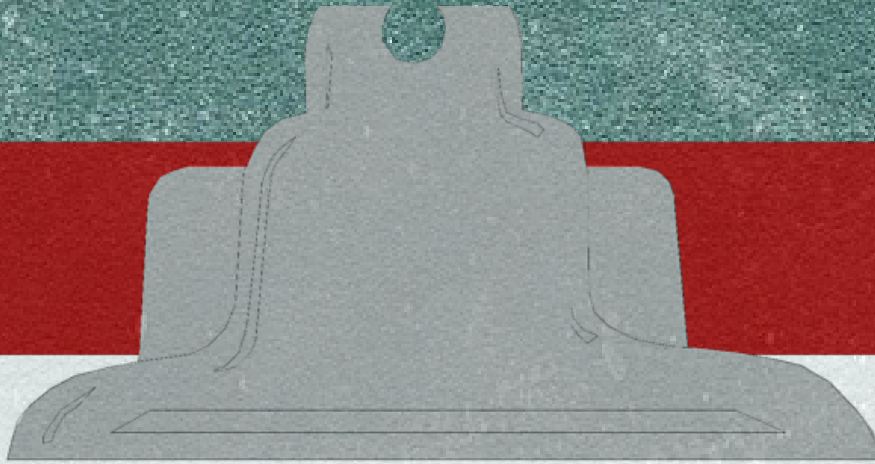
2. माता-पिता को अपने बच्चों को किसी भी कठिनाई के बावजूद स्कूली शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

3. जो छात्र अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहते हैं उन्हें अंशकालिक नौकरी करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

5. समाचारों और मीडिया में यह बताया गया है कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए आरक्षित कई सीटें अभी भी खाली हैं। हमें अपनी बेहतरी और सफलता के लिए हमारे लिए बने अवसरों का लाभ उठाना याद रखना चाहिए।

7. यह हमारे जैसे अन्य लोगों और हमारी युवा पीढ़ी को भी हमारे नक्शेकदम पर चलने और अपना जीवन बदलने के लिए प्रेरित करता है।

भारत में शिक्षा के लिए योजनाएँ



सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)-

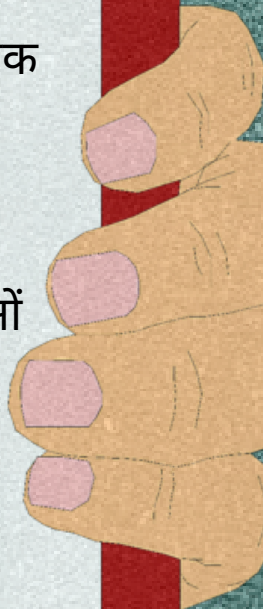
2001 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश में प्रारंभिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। यह नामांकन बढ़ाने, प्रवेश प्रबंधन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा में लिंग और सामाजिक असमानताओं को कम करने पर केंद्रित है। यह योजना नए स्कूलों के निर्माण, अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों और पीने के पानी की सुविधाओं के साथ-साथ अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है।

मध्याह्न भोजन योजना

1995 में शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना, सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को मुफ्त गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के नामांकन, ठहराव और उपस्थिति में सुधार करना है, साथ ही बच्चों में कुपोषण से निपटना है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

2009 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश में माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। यह योजना नए माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण, अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों और पीने के पानी की सुविधाओं के साथ-साथ अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है।





माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई)

2008 में शुरू की गई यह योजना आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समूहों की छात्राओं के परिवारों को उनकी माध्यमिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन और ठहराव में सुधार करना है।

माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईडीएसएस)

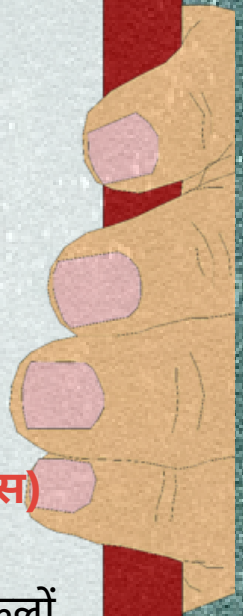
2009 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना नए समावेशी स्कूलों, अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों और पीने के पानी की सुविधाओं के निर्माण के साथ-साथ अतिरिक्त शिक्षकों और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में वंचित पृष्ठभूमि, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों के निर्माण का प्रावधान करती है।

समग्र शिक्षा

2018 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना और प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना तीन मौजूदा योजनाओं - सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को समाहित करती है।





प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)

2008 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन और ठहराव में सुधार करना है। यह योजना नए प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण, अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों और पीने के पानी की सुविधाओं के साथ-साथ अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है।

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएस)

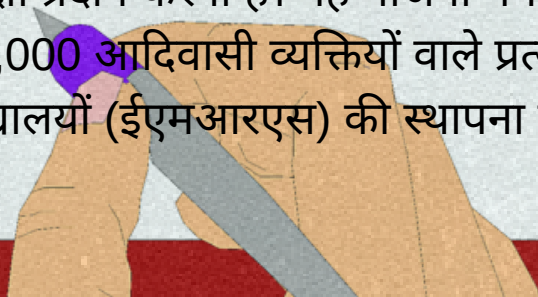
2008 में शुरू की गई यह योजना आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। यह छात्रवृत्ति कक्षा 8 और 9 में पढ़ने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है और इसका उद्देश्य छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने और अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएसई)

1963 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश में छात्रों के बीच प्रतिभा की पहचान करना और उसका पोषण करना है। यह योजना 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित करती है और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

2018 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य दूरदराज और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना पर्याप्त एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना का प्रावधान करती है।





विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (IEDC)

1974 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना विशेष स्कूलों, अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों और पीने के पानी की सुविधाओं के निर्माण के साथ-साथ अतिरिक्त शिक्षकों और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस)

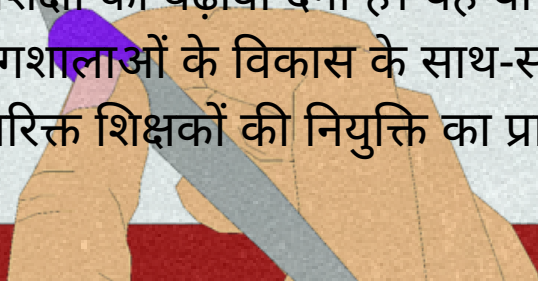
2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश में छात्रों के सीखने के स्तर की सटीक तस्वीर प्रदान करना है। सर्वेक्षण कक्षा 3, 5 और 8 के छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है और विभिन्न विषयों में छात्रों के सीखने के स्तर के साथ-साथ उन क्षेत्रों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रदान करता है जहां छात्रों को सुधार की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ)

2005 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देश में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम के विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। एनसीएफ पाठ्यक्रम के विकास के साथ-साथ छात्रों के मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए)

2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्कूलों में विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना स्कूलों में विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं के विकास के साथ-साथ विज्ञान और गणित के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है।



कौशल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईएस)

2009 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्कूलों में छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करती है।

पढ़े भारत बड़े भारत (पीबीबीबी)

2018 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों के पढ़ने, लिखने और अंकगणित कौशल में सुधार करना है। यह योजना शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने, पढ़ने की सामग्री विकसित करने और स्कूलों में पढ़ने की संस्कृति बनाने पर केंद्रित है।

